स्वप्रेरणा अवमानना याचिका (सीआरएल संख्या 5/2017)

मोहित चौधरी, अधिवक्ता

17 अगस्त 2017

[जगदीश सिंह खेहर, सीजेआई, डॉ. डी.वाई. चंद्रचूड़ और संजय किशन कौल, जे.जे]

न्यायालय की अवमानना एडवोकेट-ऑन-रिकॉर्ड द्वारा कदाचार -

अवमाननाकर्ता-एडवोकेट-ऑन-रिकॉर्ड ने न्यायालय के समक्ष उल्लेख किया उन्होंने बेहद उत्तेजित और आक्रामक अंदाज में ऐसा आरोप लगाया भारत के सर्वोच्च न्यायालय की रजिस्ट्री ने विपरीत वादी के साथ मिलीभगत की बेंच हंटिंग के उद्देश्य से मामले को जल्दबाज़ी में सूचीबद्ध करने की मांग की गई के संबंध में उनके द्वारा मुख्य न्यायाधीश को लिखा गया एक पत्र प्रस्तुत किया गया वही मुद्दा - माना गया: अवमाननाकर्ता 2009 से एक एडवोकेट-ऑन-रिकॉर्ड के रूप में अभ्यास कर रहा है - वह प्रतिष्ठित संस्थान, राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और जाहिर तौर पर काफी शांत है इस न्यायालय की प्रथाओं से परिचित - ऐसा नहीं कहा जा सकता इस तथ्य से बेखबर कि रजिस्ट्री द्वारा कोई बेंच गठित नहीं की जाती है, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा - इस प्रकार, अप्रत्यक्ष रूप से तरीके से, प्रमुख के खिलाफ भी एक आरोप लगाया गया था हालाँकि न्याय रजिस्ट्री पर एक ज़बरदस्त हमले की आड़ में है - प्रश्नगत पत्र में दिए गए दावे स्पष्ट रूप से झूठे थे - बेंच में कोई बदलाव नहीं हुआ और न ही मामला स्पेशल के सामने रखा गया बेंच, जैसा कि आरोप लगाया गया है - जहाँ तक लिस्टिंग का सवाल है, अगर अनजाने में मामला अग्रिम सूची से हटा दिया गया था लेकिन फिर से सूची में सामने आया था, पिछले आदेश को देखते हुए यह कोई आश्चर्य की बात नहीं थी - ऐसा नहीं था एक मामला जहां एक एडवोकेट-

ऑन-रिकॉर्ड कुछ कठिनाई व्यक्त कर रहा था होने के कारण मामले का प्रतिनिधित्व करने की मांग में लिस्टिंग से अनजान - इसके अलावा, मामले के रिकॉर्ड से पता चलता है मूल रिट याचिका एक अन्य एडवोकेट-ऑनरिकॉर्ड के माध्यम से दायर की गई थी, लेकिन अवमाननाकर्ता सुनवाई की पहली तारीख पर उपस्थित हुआ इसके बाद तीन अन्य एडवोकेट-ऑन-रिकॉर्ड्स उनके उत्तराधिकारी बने - इसके बाद, याचिकाकर्ता ने फिर से उस अवमाननाकर्ता को शामिल किया जो मामले का उल्लेख करने के समय सामने आया था - यह स्पष्ट है कि पूर्व एडवोकेट-ऑन-रिकॉर्ड ने वादी याचिकाकर्ता को उपकृत करने से इनकार कर दिया था न्यायालय के समक्ष अनुचित उल्लेख करने के लिए - यह है अवमाननाकर्ता जिसने दृश्य में फिर से प्रवेश करने के अवसर का उपयोग किया पीठ के प्रयास में याचिकाकर्ता की सहायता करने का उद्देश्य आरोपों और आक्षेपों की आड़ में शिकार किया गया

पंजीकरण के विरुद्ध- अवमानकर्ता ने इस प्रकार वादकारी के हाथों में एक प्यादा होने का, न्यायालय और पंजीकरण को बदनाम करने का एक सचेत निर्णय लिया-सर्वोच्च न्यायालय में रिकॉर्ड पर अधिवक्ता की तुलना में एक अधिवक्ता का आचरण बहुत कम अशोभनीय था-'इस प्रकार, अवमानकर्ता को अधिवक्ता-पर-अधिवक्ता के रूप में अभ्यास करने की अनुमति नहीं थी। एक महीने की अवधि के लिए अभिलेख-अधिवक्ता-उच्चतम न्यायालय नियम, का 2013-10, Or.IV - भारतीय विधिज्ञ परिषद नियम-अध्याय II, भाग-VI।

अधिवक्ता-व्यावसायिक आचरण और शिष्टाचार के मानक-चर्चा की गई।

अभिनिर्धारित किया-

1. अवमानक एक अधिवक्ता-ऑन-रिकॉर्ड है जो वर्ष 2009 से उस क्षमता में अभ्यास कर रहा है-इस क्षेत्र में नौसिखिया नहीं है। वह प्रतिष्ठित संस्थानों, राज्य सरकार और प्राधिकरणों का प्रतिनिधित्व करते रहे हैं और स्पष्ट रूप से इस न्यायालय की प्रथाओं से काफी परिचित हैं। उन्हें इस तथ्य से अनजान नहीं कहा जा सकता है

कि पंजीकरण द्वारा कोई पीठ का गठन नहीं किया जाता है, बल्कि इस न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा किया जाता है। इस प्रकार, अप्रत्यक्ष रूप से, मुख्य न्यायाधीश के खिलाफ भी एक आरोप लगाया गया था, हालांकि पंजीकरण पर एक उग्र हमले की आड़ में। [पैरा 4] [(771-ए-बी]

2. पत्र में कथन स्पष्ट रूप से गलत थे क्योंकि 31.3.2017 पर मामले को 7.4.2017 पर सूचीबद्ध करने के लिए विशिष्ट निर्देश जारी किए गए थे, "अंत में सुनवाई के लिए" इस प्रकार, यदि अनजाने में मामला अग्रिम सूची से हटा दिया गया था, लेकिन सूची में फिर से दिखाई दिया था, तो अंतिम आदेश को देखते हुए कोई भी आश्चर्यचकित नहीं हो सकता था। यह ऐसा मामला भी नहीं था जिसमें रिकॉर्ड पर अधिवक्ता सूचीकरण से अनजान होने के कारण मामले का प्रतिनिधित्व करने की मांग करने में कुछ कठिनाई व्यक्त कर रहा था, इस मामले में, कुछ समायोजन के लिए संबंधित पीठ के समक्ष अनुरोध किया जाएगा। [पैरा 6] [771-डी-ई]

3. न्यायालय में दिनांक 31-03-2017 पर प्रस्तुत आदेश संयोग से उसी पीठ द्वारा पारित किया गया था जिसके समक्ष मामला 07-04-2017 को सूचीबद्ध था, और इस प्रकार, पीठ में भी कोई बदलाव नहीं हुआ था, न ही मामले को विशेष पीठ के समक्ष रखा गया था। इसे नियमित पीठ के सामने सूचीबद्ध किया गया था। इसे किसी विशेष पीठ के समक्ष सूचीबद्ध नहीं किया गया था।

अवमानकर्ता के पत्र के साथ "बेंच हंट" से संबंधित कुछ लेख भी थे, जिसमें अवमानकर्ता के हमले की दिशा के बारे में कोई संदेह नहीं था। [पैरा 7। [771-जी-एच]

4. सूचीकरण न्यायिक निर्देश पर आधारित था और न्यायालय की पंजीकरण के हाथों निर्धारित नहीं किया गया था। पंजीकरण के खिलाफ न्यायाधीशों के खिलाफ भी

निर्देशित आक्षेपों के साथ लगाए जाने वाले आरोपों से प्रथमदृष्टया संतोष होता है कि रिकॉर्ड पर अधिवक्ता ने इस तरह के आक्षेप और आरोप लगाकर अदालत की अवमानना की थी। [पैरा 8] [772-ए-बी।

5. इसके अलावा, मामले के रिकॉर्ड से पता चलता है कि मूल सी. रिट याचिका एक अन्य अधिवक्ता-ऑन-रिकॉर्ड द्वारा से दायर की गई थी, लेकिन अवमाननाकर्ता सुनवाई की तारीख पहली तारीख को पेश हुआ। इसके बाद, तीन अन्य अधिवक्ता-ऑन-रिकॉर्ड उनके उत्तराधिकारी बने और 04.04.2017 तक बने रहे। याचिकाकर्ता ने फिर से अवमानकर्ता को नियुक्त किया जो इतने समय तक घटनास्थल से दूर रहने के बाद उल्लेख करने के लिए आया था। पूर्व अधिवक्ता-ऑन-रिकॉर्ड 31.03.2017 पर बना रहा जब मामले को 07.04.2017 पर अंतिम निपटान के लिए सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया गया था। 07.04.2017 पर भी अवमाननाकर्ता के अलावा एक अन्य अधिवक्ता की उपस्थिति दर्ज की जाती है जब मामले को पीठ द्वारा लिया गया था और याचिकाओं को खारिज कर दिया गया था। [पैरा 14] [776-डी-ई]

6. यह बिल्कुल स्पष्ट है कि परिदृश्य यह था कि मौजूदा अधिवक्ता-ऑन-रिकॉर्ड ने वादकारी याचिकाकर्ता को अदालत के समक्ष अनुचित उल्लेख करने के लिए बाध्य करने से इनकार कर दिया, जैसा कि अवमानक द्वारा प्रयास किया गया था, जिसमें मामले को मौजूदा पीठ से बाहर स्थानांतरित करने की मांग की गई थी। यह अवमानकर्ता ही है जिसने पंजीकरण और उस मामले के लिए, यहां तक कि अदालत के खिलाफ लगाए गए आरोपों और आक्षेपों की आड़ में, इस तरह की पीठ की खोज के प्रयास में याचिकाकर्ता की सहायता करने के उद्देश्य से, दृश्य में फिर से प्रवेश करने के लिए अवसर का उपयोग किया। अवमानकर्ता ने इस प्रकार एक पीठ स्थानांतरण प्राप्त करने के एकमात्र उद्देश्य के साथ, न्यायालय और न्यायालय की पंजीकरण को बदनाम

करने के लिए, वादकारी के हाथों में एक प्यादा होने का एक सचेत निर्णय लिया। यह स्पष्ट रूप से उनके मुवक्किल के हित को कम करने के लिए एक "व्यावसायिक निर्णय" था, भले ही, यह झूठे आरोपों के बराबर होगा और एक अधिवक्ता के लिए अशोभनीय होगा। [पैरा 15] [776-एफ-एच]

7. एक अधिवक्ता का कर्तव्य है कि वह वादकारी के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ मामला न्यायालय के समक्ष रखे। हालाँकि, यह उन्हें न्यायालय के एक अधिकारी के रूप में जिम्मेदारी से मुक्त नहीं करता है। यह दोहरी जिम्मेदारी है। उच्चतम न्यायालय में रिकॉर्ड पर अधिवक्ता का अधिकार, बार में नामांकन से आने वाला एक स्वचालित अधिकार नहीं है। कुछ और करना होगा। एक परीक्षा की कठोरताओं द्वारा गुजरना पड़ता है, जो अधिवक्ता की न केवल कानून का मसौदा तैयार करने और उसके ज्ञान की कानूनी योग्यता पर, बल्कि नैतिक प्रथाओं पर भी परीक्षण करता है। कठोर अभ्यास द्वारा गुजरने के बाद ही एक अधिवक्ता को रिकॉर्ड पर अधिवक्ता के रूप में सूचीबद्ध किया जाता है, जिसद्वारा उद्वारा सर्वोच्च न्यायालय के नियम, 2013 के अनुरूप इस न्यायालय के समक्ष कार्य करने और अभिवचन दायर करने का अधिकार मिलता है। [पैरा 16] [777-ए-सी]

8. यह एक निर्दोष कार्य नहीं था, एक हानिरहित प्रयास था, बल्कि एक दुर्भाग्यपूर्ण रास्ते पर चलने का एक सुविचारित निर्णय था, जिसे मौजूदा रिकॉर्ड पर अधिवक्ता करने के लिए तैयार नहीं थे। इसका उद्देश्य केवल किसी तरह पीठ को स्थानांतरित करने की मांग करके मुवक्किल की सहायता करना था। पंजीकरण के खिलाफ लगाए गए आरोप झूठे थे और अदालत के खिलाफ आरोप थे। यह प्रयास विफल रहा। प्रत्येक क्रिया का एक परिणाम होता है। इस प्रकार अवमानकर्ता को अपने आचरण के कुछ परिणामों का सामना करना पड़ता है। होने का विशेषाधिकार नियमों के

तहत रिकॉर्ड पर अधिवक्ता का स्पष्ट रूप से अवमानकर्ता द्वारा दुरुपयोग किया गया है। यह आचरण सर्वोच्च न्यायालय में एक अधिवक्ता से बहुत कम एक अधिवक्ता-ऑन-रिकॉर्ड नहीं बन रहा था। [पारस 29,30] [782-जी-एच; 783-ए]

9. आदेश 4 नियम 10 के परंतुक की पूर्व-आवश्यकताएँ, मुख्य न्यायाधीश द्वारा पीठ का गठन किए जाने के कारण और अवमानकर्ता को अधिक गंभीर परिणामों के बारे में पता होने के कारण, जो उसके सामने आ सकते थे, जिन्हें उनका अनुसरण करना होता है। उचित कार्रवाई यह होगी कि अवमानकर्ता को आदेश की तारीख से एक महीने की अवधि के लिए रिकॉर्ड पर अधिवक्ता के रूप में अभ्यास करने की अनुमति नहीं है। [पैरा 31,32] [784-बी-सी]

विनय चंद्र मिश्रा, पुनः (1995) 2 एस. सी. सी. 584; [1995] 2 एस. सी. आर. 638; सम्राट बनाम रजनीकांत बोस 49 सी. ए. एल. 732; 71 इंड केस 81; संजीव दत्ता, डिप्टी कमिश्नर। सिकरी। सूचना और प्रसारण मंत्रालय, पुनः (1995) 3 एस. सी. सी. 619; [1995] 3 एस. सी. आर. 450;2. बनाम ओ 'कोनेल 7 आयरिश लॉ रिपोर्ट 313; बार काउंसिल ऑफ महाराष्ट्र बनाम एम. वी. दाभोलकर (1976) 2 एस. सी. सी. 291:[1976] 2 एस. सी. आर. 48; 'जी' सर्वोच्च न्यायालय के एक वरिष्ठ अधिवक्ता, ए. आई. आर. 1954 एस. सी. 557 में-संदर्भित। वर्जीनिया लॉ रिव्यू, Vol.11, नंबर 4 (फरवरी 1925) पीपी. 263-277; वारवेल्स लीगल एथिक्स, पृष्ठ 182 पर दूसरा संस्करण-संदर्भित।

मामला कानून संदर्भ

[1995] 2 एस.सी.आर. 638 में निर्दिष्ट पैरा 18

49 सी. एल. 732 में निर्दिष्ट अनुच्छेद 19

[1995] 3 एस.सी.आर. 450 में निर्दिष्ट पैरा 21

7 आयरिश विधि रिपोर्ट 313 में निर्दिष्ट पैरा 24

[1976] 2 एस. सी. आर. 48 में निर्दिष्ट पैरा 25

ए.आई. आर.1954 एस.सी.557 को संदर्भित पैरा 26

आपराधिक मूल क्षेत्राधिकार 2017 का सुओ मोटो अवमानना याचिका (आपराधिक) सं. 5।

ए. जी., के. के. वेणुगोपाल, सलमान खुर्शीद, आर. एस. सूरी, सिद्धार्थ लूथरा, कॉलिन गोंजाल्विस, अजीत कुमार सिन्हा, वरिष्ठ अधिवक्ता। , गोपाल सिंह, गौरव भाटिया, कुणाल सचदेवा, इमरान, नितिन मिश्रा, अधिवक्ता। समकालीन के लिए।

मोहित चौधरी (व्यक्तिगत रूप से)।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

संजय किशन कौल, जे. 1.एक महान पेशा। न्यायालय का एक अधिकारी। उच्चतम न्यायालय नियम, 2013 के तहत उस ओर से प्रदत्त विशेषाधिकार रखने वाला रिकॉर्ड पर अधिवक्ता। और अवमानना कार्यवाही में अवमानक के रूप में प्रस्तुत ऐसे अधिवक्ता के आचरण पर गौर करना न्यायालय का एक दर्दनाक कार्य है।

2. 07.04.2017 को सुबह 10.30 पर, हमारा सामना श्री मोहित चौधरी, अधिवक्ता-ऑन-रिकॉर्ड से हुआ, जिन्होंने बेहद उत्तेजित और आक्रामक तरीके से पहला उल्लेख किया। उन्होंने यह तर्क देना चाहा कि "बेंच हंट" के उद्देश्य से विरोधी पक्ष का पक्ष लेने के आदेश इस न्यायालय की पंजीकरण में एक बड़ी हेराफेरी हुई थी। उन्होंने अदालत के समक्ष उल्लेख के दौरान 07.04.2017 दिनांकित एक पत्र पेश करने की

मांग की, जिसे संलग्नक के रूप में रिकॉर्ड में लिया गया था। उक्त पत्र की सराहना आदेशने के लिए, हम इसे निम्नानुसार पुनः प्रस्तुत आदेशते हैंः

"को

भारत के सर्वोच्च न्यायालय के माननीय

मुख्य न्यायाधीश, नई दिल्ली

संदर्भः 2015 की अवमानना याचिका (सिविल) No.785 और 2013 की SLP (C) No.31520।

संबंधित मामलों के साथ-साथ

उपःपीठ शिकार के एकमात्र उद्देश्य के साथ भारी मात्रा में पदार्थों को अप्राकृतिक और जल्दबाजी में सूचीबद्ध करने के कार्य की जांच।

मेरे स्वामी,

पीठ हंट के उद्देश्य से बेईमान वादियों द्वारा स्थापित एक दुर्भाग्यपूर्ण, संस्थागत विरोधी और जोड़-तोड़ की प्रवृत्ति ने इस शिकायत को जन्म दिया है।

उपरोक्त मामले कोलाबा में दक्षिण मुंबई में 33 एकड़ भूमि पर एस. आर. ए. परियोजना से संबंधित हैं, विवाद का रूढ़िवादी मूल्यांकन लगभग Rs.5000 करोड़ होगा। इस न्यायालय द्वारा पारित अंतरिम आदेशों के बावजूद विभाग के वरिष्ठ अधिकारी बड़े कॉर्पोरेट के हाथों में खेल रहे हैं, जानबूझकर अवमानना के कार्य में लिप्त हैं। बीमारी की बात लंबित हैं,

इन घटनाओं के बारे में कुछ चिंताजनक विवरण कल शाम (लगभग 1 बजे) सामने आए, जब पूरक सूची में आज एक विशेष पीठ (जिसमें एच. एम. जे. शामिल

है) में भारी मात्रा में मामले (रिपोर्ट/अध्ययन आदि के साथ लगभग 12000 पृष्ठ) को सूचीबद्ध दिखाया गया। अरुण मिश्रा और एच. एम. जे. एस. अब्दुल नजीर) मामले की आंशिक सुनवाई या अन्यथा उक्त पीठ के लिए चिह्नित नहीं होने के बावजूद। व्यवसाय के सामान्य पाठ्यक्रम में "मामला" एक नियमित पीठ में जाना चाहिए था।

नियमित पीठ के समक्ष मामले को सूचीबद्ध करने और एक विशेष पीठ के गठन में लिप्त होने के सामान्य नियम से विचलन में, ग्यारहवें घंटे पर पंजीकरण की ओर से गैर-पारंपरिक और शरारती कार्य है। यह और भी बदतर हो जाता है, क्योंकि 18.28 बजे जारी की गई 'उन्मूलन सूची' के अनुसार इस मामले को 07.04.2017 की अग्रिम वाद सूची से हटा दिया गया था। इस प्रकार, किसी मामले को एक शाम पहले रखने से मुंबई में स्थित पार्टी और दिल्ली में परामर्श को तैयारी करने के लिए कोई समय नहीं मिल रहा है।

एक जांच की जानी चाहिए और अभ्यास निर्देश दिया जाना चाहिए। विशेष रूप से ऐसे सभी विशाल और उच्च हिस्सेदारी वाले मामलों के संबंध में जारी किया जाता है जहां पक्ष दूर के स्थानों से हैं और उन्हें सूचीबद्ध करने के लिए पर्याप्त सूचना की आवश्यकता होती है। वर्तमान मामले में गंभीर मुद्दे उठते हैं।

इस मामले को अस्वाभाविक जल्दबाजी में और पक्षकारों/वकीलों को पर्याप्त नोटिस दिए बिना और विशेष पीठ के समक्ष भी, नियमित पीठ से हटकर, न्यायिक औचित्य और शिष्टाचार का उल्लंघन करते हुए क्यों सूचीबद्ध किया गया है?

क्या कोई वकील/पक्ष या कोई भी माननीय न्यायाधीश अन्य पक्षों को नोटिस दिए बिना अनुरोध कर सकता है कि मामले को हटाने के बावजूद इसे शामिल किया जाए?

ऊपर दिए गए परेशान करने वाले तथ्यों के समूह में, अनुरोध किया जाता है

कि विषय को नियमित पीठ या माननीय मुख्य न्यायाधीश के न्यायालय के समक्ष रखा जाए और सख्त अभ्यास निर्देश जारी किए जाएं, क्योंकि न केवल वर्तमान मामले में, बल्कि अतीत में पंजीकरण भी अतीत में इस तरह के कदाचार में लिप्त रही है (संदर्भ सिडको और एच. डी. सुधाकर बनाम को दिया गया है। मेट्रोपोलिस होटल मामले)।

द्वारा प्रस्तुत किया गयाः

एसडी/-

मोहित चौधरी

रिकॉर्ड के लिए अधिवक्ता

याचिकाकर्ता-स्वयं रूप से

तारीखः04.07.2017

नई दिल्ली

एसडी/-

याचिकाकर्ता "

(जोर दिया गया)

3. इस प्रकार आरोप स्पष्ट और स्पष्ट है-पंजीकरण ने पीठ हंट के उद्देश्य से मामले को जल्दबाजी में सूचीबद्ध करने के लिए विरोधी वादकारी के साथ मिलीभगत की थी। इसे "एक दुर्भाग्यपूर्ण और संस्थागत विरोधी और जोड़-तोड़ की प्रवृत्ति" के रूप में वर्गीकृत किया गया था, जो इस बात का संकेत देता है कि मामला अचानक शाम की सूची में विशेष पीठ के समक्ष पूरक मामले के रूप में दिखाई दिया था, इसके बावजूद कि मामले की 'आंशिक सुनवाई' नहीं की गई थी या अन्यथा पीठ के लिए चिह्नित नहीं किया गया था। यह एक नियमित पीठ के समक्ष सूचीबद्ध करने के सामान्य नियम का

उल्लंघन और पंजीकरण की ओर से एक गैर-पारंपरिक और शरारतपूर्ण कार्य के रूप में ग्यारहवें घंटे में एक विशेष पीठ का गठन करने में लिप्त होने का आरोप लगाया गया था। यह इस तथ्य के बावजूद था कि इस मामले को पहले 07.04.2017 की अग्रिम कारण सूची से हटा दिया गया था।

4. हम ध्यान दे सकते हैं कि अवमानकर्ता वर्ष 2009 से उस क्षमता में अभ्यास करने वाला एक अधिवक्ता-ऑन-ध्यान दें है-इस क्षेत्र में नौसिखिया नहीं है। वह प्रतिष्ठित संस्थानों, राज्य सरकार और प्राधिकरणों का प्रतिनिधित्व करते रहे हैं और स्पष्ट रूप से इस न्यायालय की प्रथाओं से काफी परिचित हैं। उन्हें इस तथ्य से अनजान नहीं कहा जा सकता है कि पंजीकरण द्वारा कोई पीठ का गठन नहीं किया जाता है, बल्कि इस न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा किया जाता है। इस प्रकार, 2 "अप्रत्यक्ष तरीके से, मुख्य न्यायाधीश के खिलाफ भी एक आरोप लगाया गया था, हालांकि पंजीकरण पर एक उग्र हमले की आड़ में।

5. "परेशान करने वाले तथ्यों" को ध्यान में रखते हुए पत्र में की गई प्रार्थना थी कि मामले को एक नियमित पीठ के समक्ष रखा जाए और "सख्त अभ्यास निर्देश" जारी किए जाएं ताकि पंजीकरण को "इस तरह के कदाचार" में लिप्त होने से रोका जा सके, जैसा कि पंजीकरण ने अतीत में भी किया है। कदाचार "।

6. कम से कम कहने के लिए, हम न केवल पत्र की सामग्री से, बल्कि अदालत में प्रस्तुत करने के तरीके से भी चकित थे। हमारी खोज से पता चला कि पत्र में कथन स्पष्ट रूप से गलत थे क्योंकि 31.3.2017 पर मामले को 7.4.2017 पर सूचीबद्ध करने के लिए विशिष्ट निर्देश जारी किए गए थे, "अंत में सुनवाई के लिए। " इस प्रकार, यदि अनजाने में मामला अग्रिम सूची से हटा दिया गया था, लेकिन सूची में फिर से दिखाई दिया था, तो अंतिम आदेश को देखते हुए कोई भी आश्चर्यचकित नहीं हो

सकता था। यह ऐसा मामला भी नहीं था जिसमें रिकॉर्ड पर अधिवक्ता सूचीकरण से अनजान होने के कारण मामले का प्रतिनिधित्व करने में कुछ कठिनाई व्यक्त कर रहा था, इस मामले में, कुछ समायोजन के लिए संबंधित पीठ के समक्ष अनुरोध किया जाएगा। इरादा साफ था। जिस पीठ के समक्ष मामला सूचीबद्ध था, वह याचिकाकर्ता और अधिवक्ता-ऑन-रिकॉर्ड को सबसे अच्छी तरह से ज्ञात कारणों से मामले की सुनवाई नहीं कर सकी। इस प्रकार जूता दूसरे पैर पर था यानी पीठ शिकार का एक प्रयास-हमारे सामने उल्लेख किए गए वादकारी द्वारा और उस प्रयास के लिए अपना कंधा रिकॉर्ड करने वाले अधिवक्ता द्वारा।

7. न्यायालय में दिनांक 31-03-2017 पर प्रस्तुत आदेश संयोग से उसी पीठ द्वारा पारित किया गया था जिसके समक्ष मामला 07-04-2017 पर सूचीबद्ध था, और इस प्रकार, पीठ में भी कोई बदलाव नहीं हुआ था, न ही मामले को विशेष पीठ के समक्ष रखा गया था। इसे नियमित पीठ के समक्ष सूचीबद्ध किया गया था। इसे किसी विशेष पीठ के समक्ष सूचीबद्ध नहीं किया गया था। अवमानकर्ता के पत्र के साथ "बेंच हंट" से संबंधित कुछ लेख भी थे, जिसमें हमले की दिशा के बारे में कोई संदेह नहीं था।

सम्माननीय।

8. हमने इसे छोड़ने की बात नहीं मानी। सूचीकरण न्यायिक निर्देश पर आधारित था और न्यायालय की पंजीकरण के हाथों निर्धारित नहीं किया गया था। पंजीकरण के खिलाफ न्यायाधीशों के खिलाफ भी निर्देशित आक्षेपों के साथ लगाए जाने वाले आरोपों से हमें प्रथमदृष्टया संतोष हुआ कि अधिवक्ता-ऑन-रिकॉर्ड ने इस तरह के आक्षेप और आरोप लगाकर अदालत के सामने अवमानना की और इस प्रकार अवमानना का नोटिस तब और वहां जारी किया गया, जिसमें श्री मोहित चौधरी को इस ओर से

एक शपथ पत्र दायर करने की स्वतंत्रता दी गई। इस मामले को 10 अप्रैल, 2017 के लिए पोस्ट किया गया था।

9. अदालत के सामने अवमानना की कार्यवाही का सामना करने वाले अवमानकर्ता ने उसी तारीख को अदालत के समक्ष एक शपथ पत्र दायर करने की मांग करते हुए पीछे हटने की कोशिश की। अवमानकर्ता द्वारा "मेरी जानकारी और विश्वास के लिए सही और सही" के रूप में सत्यापित शपथ पत्र में, यह पुष्टि की गई थी कि मुवक्किल के हित का प्रतिनिधित्व करते हुए उन्होंने अदालत के समक्ष एक उल्लेख किया था, जो उनके अनुसार, उनके निर्णय का सर्वश्रेष्ठ था, एकमात्र उपलब्ध मार्ग था। हम शपथ पत्र को निम्नानुसार पुनः प्रस्तुत करते हैंः-

"को।

भारत के माननीय मुख्य न्यायाधीश

और उनके साथी न्यायाधीश

सुप्रीम कोर्ट, नई दिल्ली

शपथ पत्र

मैं मोहित चौधरी पुत्र स्वर्गीय श्री आर. के. चौधरी, निवासी बी-180, पूर्व कैलाश, नई दिल्ली, 40 वर्ष की आयु में, निम्नलिखित रूप में गंभीरता से पुष्टि करता हूंः

1. सबसे पहले, मैं कहता हूं कि मैं भारत की न्यायिक प्रणाली और इस माननीय न्यायालय के प्रति सर्वोच्च सम्मान रखता हूं। मैं इस न्यायालय का अभिलेख पर अधिवक्ता हूँ। आज मैं जो कुछ भी हूं (अपनी पहचान के संदर्भ में) वह न्यायालय का एक अधिकारी होने के कारण है, इसलिए मैं कभी भी अपने सपने में भी न्यायालय की गरिमा और महिमा की अवहेलना करने

की हिम्मत या प्रयास नहीं कर सकता।

2. हालाँकि, न्यायालय का एक अधिकारी होने के नाते और अपने मुवक्किल के हित का प्रतिनिधित्व करते हुए (इसमें कुछ भी व्यक्तिगत नहीं होने के कारण), मैंने इस माननीय न्यायालय के समक्ष एक उल्लेख किया, जो मेरे निर्णय के अनुसार एकमात्र उपलब्ध मार्ग था। इस न्यायालय से अभ्यास निर्देश जारी आदेशने का अनुरोध आदेशने के लिए (उस मामले को सूचीबद्ध आदेशने के लिए जहां पक्षों को पर्याप्त नोटिस दिया जा सकता था), लालसो ने ए ओवर शिकायत को माननीय न्यायालय को सौंप दिया। उक्त शिकायत की प्रति केवल मेरे पास और माननीय न्यायालय के पास है।

3. हालाँकि, ऐसा प्रतीत होता है कि मेरा दृष्टिकोण उचित नहीं था और इस प्रकार अपनी बात रखने के आदेश, मुझे लगता है कि

क. मैं अपने उक्त कृत्य के लिए बहुत माफी मांगता हूं जिसने इस माननीय न्यायालय को यह आभास दिया कि मैं अवमानना के कार्य में लिप्त हूं। यहां तक कि मैंने खुली अदालत में अपनी माफी भी मांगी, माननीय अदालत ने मुझे अवमानना नोटिस जारी करने का प्रथमदृष्टया विचार लिया।

ख. इस न्यायालय में मैंने भारत संघ, सार्वजनिक उपक्रमों और विभिन्न प्रकार के ग्राहकों के लिए काम किया है और यहां तक कि मुझे जम्मू-कश्मीर राज्य के लिए अतिरिक्त सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों रूप में नियुक्त किया जा रहा था, कहीं भी मेरी शिकायत नहीं है।

4. अंत में, मैं फिर से अपने अनजाने में किए गए कृत्य के लिए अपनी बिना शर्त डी माफी प्रस्तुत करना चाहता हूं। आपके स्वामी इस मामले में उदार दृष्टिकोण अपना सकते हैं और मुझे क्षमा कर सकते हैं।

प्रतिपादक

सत्यापन

मैं कहता हूं कि मेरे शपथ पत्र की उपरोक्त सामग्री सही और सही है। मेरे ज्ञान और विस्वाक्ष के लिए

नई दिल्ली में 07.04.2017 पर सत्यापित।

प्रतिपादक "

10. शपथ पत्र में अपनाई गई स्थिति को शायद ही बिना शर्त माफी के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है, क्योंकि यह इस बात का औचित्य था कि अवमानकर्ता ने अतीत में क्या किया था और जो कहा गया था कि मेरा दृष्टिकोण उचित नहीं था। शपथ पत्र में व्यक्त इस स्थिति को शायद ही जी. जी. को अवमानकर्ता के कार्यों के औचित्य के रूप में स्वीकार किया जा सकता था। आगे स्पष्टीकरण दाखिल करने के लिए स्वतंत्रता मांगी गई और प्रदान की गई। अवमानकर्ता द्वारा दायर किए गए दूसरे शपथ पत्र की पुष्टि 10.4.2017 पर की गई थी। उक्त शपथ पत्र की सामग्री इस प्रकार हैः

"दिनांकित 07.04.2017 की प्रविष्टियों और पत्रों को स्वीकार करने, बिना शर्त और बिना शर्त लागू करना,"

मोहित चौधरी पुत्र स्वर्गीय श्री. R.K.Chaudhary कैलाश, नई दिल्ली के पूर्व में बी-180 के निवासी, जिनकी आयु 40 वर्ष है, वे नीचे दिए गए अनुसार गंभीरता से पुष्टि करते हैंः

1. मैं बिना किसी शर्त के इस माननीय न्यायालय से हाथ जोड़कर माफी मांगता हूं और इस माननीय न्यायालय के समक्ष 7 अप्रैल, 2017 के पत्र में बोले गए

या लिखे गए प्रत्येक शब्द को वापस लेता हूं।

2. मैं दोहराता हूं कि मेरी ओर से किसी भी तरह से या किसी भी तरह से इस माननीय न्यायालय की गरिमा का अनादर करने का कोई इरादा नहीं था। मेरा दृढ़ विश्वास है कि इस माननीय न्यायालय की गरिमा की अनुपस्थिति में में मेरी कोई गरिमा नहीं होगी। ~

3. मैंने हमेशा इस माननीय न्यायाधीशालय को सर्वोच्च सम्मान दिया है और ऐसा कुछ भी नहीं किया है जो किसी को भी न्यायाधीश देने वाली इस महान संस्था के प्रति कोई अनादर लाने के रूप में देखा जा सके।

4. मैं इस माननीय न्यायालय को विश्वास दिलाता हूं कि मैं ऐसी स्थितियों में अचानक प्रतिक्रिया के परिणामस्वरूप कभी भी कुछ नहीं करूंगा या करने का कारण नहीं बनूंगा या करने की प्रवृत्ति नहीं रखूंगा। मैं कहता हूं कि बार में बिताए कुछ वर्षों में मैंने कानून के शासन और महिमा को बनाए रखने के लिए सभी प्रयास किए हैं। इस माननीय न्यायालय या उस मामले के लिए कानून द्वारा स्थापित प्रत्येक न्यायालय की गरिमा, सम्मान मुझे बहुत प्रिय है और प्रार्थना करता हूं कि मेरी माफी स्वीकार की जाए।

5. इस माननीय न्यायालय के अनुशासन का पालन न करने ने मुझे एक सबक सिखाया है कि केवल एक मामले को सूचीबद्ध करना और वह भी माननीय न्यायालय के निर्देशों के तहत, जैसा कि मैंने कहा है, कभी भी हेरफेर नहीं किया जा सकता है और इस माननीय न्यायालय का निर्देश न केवल सभी संबंधितों के लिए बाध्यकारी था, बल्कि इस माननीय न्यायालय की पंजीकरण पर समान रूप से बाध्यकारी था।

6. 7 अप्रैल, 2017 को अपनी गलतियों और गलतियों से सीखा गया सबक

मुझे भविष्य में कोई भी राय बनाने और उस पर कार्रवाई करने से पहले ध्यान रखने में मदद करेगा। इस माननीय न्यायालय की उदारता असीम है और मैं प्रार्थना करता हूं कि आपके प्रभु इस माननीय न्यायालय के युवा अधिकारी पर उक्त उदारता दिखाएँ।

7. मैं इस माननीय न्यायालय से अनुरोध करता हूं कि वह मेरी बिना शर्त माफी को प्रतिग्रहण करना करे।

'**8**. गलती करना मानवीय है और 7 अप्रैल, 2017 को मेरे द्वारा की गई गलती ऐसी ही एक मानवीय गलती है। मैं एक बार फिर 7.4.2017 पर बोले गए और लिखे गए प्रत्येक शब्द को वापस लेता हूं और इस माननीय न्यायालय से बिना शर्त माफी मांगता हूं।

विभाग

सत्यापन

मैं उपरोक्त नामित प्रतिनिधि इसके द्वारा सत्यापित करता हूं कि उपरोक्त शपथ पत्र की सामग्री मेरी जानकारी के अनुसार सही है।

इस दिन नई दिल्ली में 10 अप्रैल, 2017 को सत्यापित किया गया

विभाग "

11. अवमानकर्ता ने अब अदालत के अनुशासन का पालन नहीं करने को स्वीकार करते हुए बिना शर्त माफी मांगने की मांग की। उन्होंने स्वीकार किया कि अदालत के निर्देश के तहत किसी मामले को सूचीबद्ध करने में कभी भी हेरफेर नहीं किया जा सकता है जैसा कि उन्होंने कहा है!अगर हम ऐसा कहें, तो इस तथ्य को जानने के लिए बहुत अधिक कल्पना और ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। अवमानकर्ता ने

अदालत के हस्तक्षेप की गुहार लगाई और 7.4.2017 पर बोले गए और लिखे गए प्रत्येक शब्द को वापस लेने की मांग करते हुए गलती करने का दावा किया और एक अयोग्य माफी मांगी।

12. 10.4.2017 पर, अदालत में दायर शपथ पत्र को रिकॉर्ड में लिया गया था, और मामले को 17.4.2017 पर आगे के विचार के लिए पोस्ट किया गया था, जिसमें अदालत के समक्ष "एसएलपी फाइल" भी रखने का निर्देश दिया गया था। 17.4.2017 पर, अवमानकर्ता का प्रतिनिधित्व करने के लिए वकीलों का एक समूह मौजूद था, जिसका नेतृत्व Mr.K.K ने किया। वेणुगोपाल, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता वकील। यह उनका तर्क था कि अवमानकर्ता ने खुद को अदालत की दया पर झोंक दिया था, और वह और कुछ नहीं कर सकता था। उन्होंने प्रस्तुत किया कि अवमानकर्ता ने गंभीर गलती की थी, लेकिन उन्होंने जो किया था, उसे याद नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार वह केवल दया की गुहार लगा सकता था। आदेश पत्र में विद्वान महान्यायवादी, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष और महान्यायवादी-ऑन-रिकॉर्ड के अध्यक्ष की उपस्थिति भी दर्ज की गई है।

13. हम इस सवाल का सामना कर रहे हैं कि ऐसी स्थिति में क्या करना सही होगा। क्या दूसरी माफी, जो बिना शर्त है, अवमानकर्ता को उसके द्वारा किए गए सभी कार्यों से दोषमुक्त करने के लिए पर्याप्त है?क्या अवमानकर्ता को अपने आचरण के लिए कुछ परिणाम भुगतने होंगे, भले ही उसके द्वारा अंततः बिना शर्त माफी मांगी गई हो?

14. इस मुद्दे को निर्धारित करने में, उपरोक्त शपथ पत्र के परिप्रेक्ष्य में, एक और महत्वपूर्ण तथ्य को ध्यान में रखा जाना चाहिए। मामले के रिकॉर्ड से पता चलता है कि मूल रिट याचिका पूजा शर्मा, अधिवक्ता-ऑन-रिकॉर्ड द्वारा से दायर की गई थी, लेकिन अवमाननाकर्ता सुनवाई की तारीख पहली तारीख को 01.10.2013 पर पेश हुआ।

पूजा शर्मा द्वारा अनापत्ति प्राप्त करने के बाद "वकालतनामा" (पावर ऑफ अटॉर्नी) को बदलकर 29.01.2014 पर श्री गौतम नारायण कर दिया गया, लेकिन इसके तुरंत बाद, अवमानकर्ता ने श्री गौतम नारायण से अनापत्ति के साथ 11.11.2014 पर "वकालतनामा" दायर किया। हालाँकि, 16.02.2015 पर श्री निर्निमेश दुबे ने प्रतिवादी अवमानक के स्थान पर एक अधिवक्ता-ऑन-रिकॉर्ड के रूप में प्रवेश किया। श्री निर्निमेश दुबे का स्थान श्री जिनेंद्र जैन ने 22.01.2016 पर लिया और 04.04.2017 तक रिकॉर्ड पर अधिवक्ता बने रहे, जब प्रतिवादी एक नया "वकालतनामा" दायर करके मामले में फिर से प्रवेश करता है। इस प्रकार, यह बिल्कुल स्पष्ट है कि याचिकाकर्ता ने अवमानकर्ता को नियुक्त किया जो इस पूरे समय के लिए घटनास्थल से दूर रहने के बाद उल्लेख करने के लिए तस्वीर में आया था। पूर्व अधिवक्ता-ऑन-रिकॉर्ड 31.03.2017 पर बना रहा जब मामले को 07.04.2017 पर अंतिम निपटान के लिए सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया गया था। यहां तक कि श्री जिनेंद्र जैन की उपस्थिति पर भी, श्री मोहित चौधरी के अलावा अधिवक्ता को दर्ज किया जाता है जब मामले को पीठ द्वारा लिया गया था और याचिकाओं को खारिज कर दिया गया था।

15. इस प्रकार हमारे लिए यह बिल्कुल स्पष्ट है कि परिदृश्य यह था कि मौजूदा अधिवक्ता-ऑन-रिकॉर्ड ने वादकारी याचिकाकर्ता को अदालत के समक्ष अनुचित उल्लेख करने के लिए बाध्य करने से इनकार कर दिया, जैसा कि अवमानक द्वारा प्रयास किया गया था, जिसमें मामले को मौजूदा पीठ से बाहर स्थानांतरित करने की मांग की गई थी। यह अवमानकर्ता ही है जिसने पंजीकरण और उस मामले के लिए, यहां तक कि अदालत के खिलाफ लगाए गए आरोपों और आक्षेपों की आड़ में, इस तरह की पीठ की खोज के प्रयास में याचिकाकर्ता की सहायता करने के उद्देश्य से दृश्य में फिर से प्रवेश करने के अवसर का उपयोग किया। अवमानकर्ता ने इस प्रकार एक पीठ स्थानांतरण प्राप्त करने के एकमात्र उद्देश्य के साथ, न्यायालय और न्यायालय की

पंजीकरण को बदनाम करने के लिए, वादकारी के हाथों में एक प्यादा होने का एक सचेत निर्णय लिया। यह स्पष्ट रूप से उनके मुवक्किल के हित को कम करने के लिए एक "व्यावसायिक निर्णय" था, भले ही, यह झूठे आरोपों के बराबर होगा और एक अधिवक्ता के लिए अशोभनीय होगा।

16. हम एक अधिवक्ता के आचरण के संबंध में कुछ न्यायिक पूर्व निर्णय और ग्रंथों की समीक्षा करना उचित समझते हैं। हम एक अधिवक्ता के कर्तव्य को स्वीकार करते हैं कि वह वादकारी के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ मामला न्यायालय के समक्ष रखे। हालाँकि, यह उन्हें न्यायालय के एक अधिकारी के रूप में जिम्मेदारी से मुक्त नहीं करता है। यह दोहरी जिम्मेदारी है। उच्चतम न्यायालय में रिकॉर्ड पर अधिवक्ता का अधिकार, बार में नामांकन से आने वाला एक स्वचालित अधिकार नहीं है। कुछ और करना होगा। एक परीक्षा की कठोरताओं द्वारा गुजरना पड़ता है, जो अधिवक्ता की न केवल कानून का मसौदा तैयार करने और कानून के ज्ञान की कानूनी योग्यता पर, बल्कि नैतिक प्रथाओं पर भी परीक्षण करता है। कठोर अभ्यास द्वारा गुजरने के बाद ही एक अधिवक्ता को रिकॉर्ड पर अधिवक्ता के रूप में सूचीबद्ध किया जाता है, जिसद्वारा उद्वारा सर्वोच्च न्यायालय के नियम, 2013 के अनुसार इस न्यायालय के समक्ष कार्य करने और अभिवचन दायर करने का अधिकार मिलता है।

17. आदेश IV, नियम 5 में निहित प्रासंगिक नियम के अवलोकन के लिए, अन्य बातों के साथ साथ साथ-साथ, परीक्षण में उपस्थित होने से पहले एक अधिवक्ता-ऑन-रिकॉर्ड के साथ एक वर्ष के लिए प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है, जिसे न्यायालय द्वारा अनुमोदित किया गया है, ताकि संभावित अधिवक्ता-ऑन-रिकॉर्ड विभिन्न पेशेवर पहलुओं में अच्छी तरह से आधारित हो। मुख्य न्यायाधीश द्वारा नियुक्त न्यायाधीशों की समिति की सामान्य नीति के तहत आयोजित अधिवक्ता-ऑन-रिकॉर्ड परीक्षा के संबंध में आवश्यकताओं के लिए सर्वोच्च न्यायालय के अभ्यास और प्रक्रिया,

प्रारूपण, वकालत और पेशेवर नैतिकता और प्रमुख मामलों में परीक्षण की आवश्यकता होती है। अवमाननाकर्ता 8 वर्षों से रिकॉर्ड पर अधिवक्ता रहा है।

18. पी. बी. सावंत के शब्दों को उधार लेने के लिए, जे. विनय चंद्र मिश्रा में, पुनः[1],

> "निर्लज्जता मुखरता नहीं है और अहंकार निडरता नहीं है। असंयमित भाषा का उपयोग अधिकार का दावा नहीं है और न ही धमकी एक तर्क है। विनम्रता दासता नहीं है और विनम्रता और विनम्रता गरिमा की कमी नहीं है। न्यायालय के प्रति आत्म-संयम और सम्मानपूर्ण दृष्टिकोण, संतुलित दिमाग के साथ और अतिशयोक्ति, दमन, विरूपण या अलंकरण के बिना सही तथ्यों और कानून की प्रस्तुति अच्छी वकालत की आवश्यकताएं हैं। एक वकील को पहले एक सज्जन होना चाहिए। उनकी सबसे मूल्यवान संपत्ति वह सम्मान और सद्भावना है जो उन्हें अपने सहयोगियों और दरबार में प्राप्त है।"

19. यह कि कानून का अभ्यास किसी अन्य व्यवसाय या पेशे के समान नहीं है क्योंकि इसमें दोहरा कर्तव्य शामिल है-न कि न्यायालय के प्रति प्राथमिक कर्तव्य और फिर मुवक्किल के लिए न्यायालय को संबोधित करने के विशेषाधिकार के साथ वादकारी के प्रति कर्तव्य सम्राट बनाम रजनीकांत बोस[2] में न्यायाधीश मुखर्जी के शब्दों में सबसे अच्छा है।

> "द प्रैक्टिस ऑफ लॉ उन सभी लोगों के लिए खुला व्यवसाय नहीं है जो इसमें शामिल होना चाहते हैं। यह एक व्यक्तिगत अधिकार या विशेषाधिकार है। यह राज्य से मताधिकार की प्रकृति में है-कि आप कानूनी पेशे के सदस्य हैं, यह आपका विशेषाधिकार है; कि आप अपने मुवक्किल का प्रतिनिधित्व कर

1 **(1995) 2 एससीसी 584**

2 **49 सी. एल. 732; 71 इंड कैस 81**

सकते हैं, यह आपका विशेषाधिकार है; कि आप उस क्षमता में अदालत में दर्शकों का दावा कर सकते हैं, यह आपका विशेषाधिकार है। आपका एक उच्च वृत्ति है जिसमें आपका विशेषाधिकार आपका कर्तव्य है और आपका कर्तव्य आपका विशेषाधिकार है। वे दोनों मेल खाते हैं। "

20. वारवेल्स लीगल एथिक्स, पृष्ठ 182 पर दूसरा संस्करण एक वकील के दायित्व को इस प्रकार निर्धारित करता हैः

"एक वकील ऐसा कुछ भी करने के लिए बाध्य नहीं है जो अदालत की गरिमा को नुकसान पहुँचाए, जिसके लिए वह स्वयं एक शपथ अधिकारी और सहायक है। उसे हर समय न्यायाधीश को सम्मानजनक सम्मान देना चाहिए और अदालत कक्ष की गरिमा का ईमानदारी से पालन करना चाहिए। "

21. अवमानना का अधिकार क्षेत्र न केवल संबंधित न्यायाधीश की प्रतिष्ठा की रक्षा करने के लिए है ताकि वह निडरता और निष्पक्षता से न्याय का प्रशासन कर सके, बल्कि "न्यायपालिका के उचित नाम" की रक्षा भी कर सके। बोलने के तरीके से संरक्षण, अपने कार्य के निष्पादन में पंजीकरण तक भी फैला हुआ है और झूठे और अनुचित आरोप जो पंजीकरण के काम में बाधा डालते हैं और इस प्रकार अप्रत्यक्ष उद्देश्यों के साथ किए गए न्यायाधीश के प्रशासन को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में संस्था के सम्मान और गरिमा को बनाए रखने के लिए न्यायालय को उन दर्दनाक आदेशतव्यों का पालन आदेशना पड़ता है जिनका हम वर्तमान कार्यवाही में सामना आदेश रहे हैं। P.B.Sawant, जे. के शब्दों में ऐसा न करने के लिए संजीव दत्ता, डिप्टी. सिकरी। ,[3] सूचना और प्रसारण मंत्रालय, फिर से, -

"वर्तमान प्रवृत्ति जब तक नियंत्रित नहीं की जाती है, तब तक एक ऐसे

3 **(1995) 3 एससीसी 619**

चरण की ओर ले जाने की संभावना है जब प्रणाली बाहर से नष्ट होने से पहले भीतर से नष्ट हो जाएगी। यह पेशे के सदस्यों के लिए है कि वे आत्मनिरीक्षण करें और समय पर सुधारात्मक कदम उठाएं और अदालतों को अप्रिय कर्तव्य से भी बचाएं। हम और नहीं कहते हैं। "

22. अब भारतीय बार काउंसिल के नियमों के "व्यावसायिक आचरण और शिष्टाचार के मानकों" की ओर मुड़ते हुए, अध्याय II, भाग VI की खंड। में निहित, न्यायालय के प्रति एक अधिवक्ता के कर्तव्यों को निर्दिष्ट किया गया है। हम नीचे दिए गए चौथे कर्तव्य को निकालते हैंः

"एक अधिवक्ता अपने मुवक्किल को तीखी या अनुचित प्रथाओं का सहारा लेने या ऐसा करने से रोकने के लिए अपने सर्वोत्तम प्रयासों का उपयोग करेगा। न्यायालय के संबंध में कुछ भी, अधिवक्ता या पक्षकारों का विरोध करना जो अधिवक्ता को स्वयं नहीं करना चाहिए। एक अधिवक्ता उस मुवक्किल का प्रतिनिधित्व करने से इनकार कर देगा जो इस तरह के अनुचित आचरण में बना रहता है। वह खुद को केवल मुवक्किल का मुखपत्र नहीं मानेगा, और पत्राचार में संयमित भाषा के उपयोग, अभिवचनों में अपमानजनक हमलों से बचने और अदालत में बहस के दौरान असंयमित भाषा का उपयोग करने में अपने स्वयं के निर्णय का प्रयोग करेगा। "

23. उपरोक्त संदर्भ में उपरोक्त सिद्धांत को अलग-अलग शब्दों में न्यायाधीश क्रैम्पटन द्वारा आर, बनाम ओ 'कोनेल[4] में निम्नानुसार निर्धारित किया गया थाः

"अधिवक्ता प्रतिनिधि होता है लेकिन प्रतिनिधि नहीं। वह अपने मुवक्किल को उसकी शिक्षा, उसकी प्रतिभा द्वारा उसके निर्णय का लाभ देता है;

4 **7 आयरिश कानून रिपोर्ट 313**

लेकिन पूरे समय वह कभी नहीं भूलता कि वह अपने द्वारा दूसरों के लिए क्या ऋणी है। वह जानबूझकर कानून को गलत नहीं बताएगा, वह जानबूझकर तथ्यों को गलत नहीं बताएगा, हालांकि यह उसके मुवक्किल के लिए मामला हासिल करने के लिए होगा। वह हमेशा इस बात को ध्यान में रखेगा कि यदि वह किसी व्यक्ति का अधिवक्ता है और उसे रखा जाता है और अक्सर अपर्याप्त रूप से पारिश्रमिक दिया जाता है, तो वह मूल्यवान है। ' सेवाएँ, फिर भी उसके पास सच्चाई और न्यायाधीश की ओर से एक पूर्व और स्थायी अनुचर है और कोई क्राउन या अन्य लाइसेंस नहीं है जो किसी भी मामले में या किसी भी पक्ष या उद्देश्य के लिए उसे उस प्राथमिक और सर्वोपरि अनुचर से मुक्त कर सके। ”

24. इस प्रकार पेशे के मूल सिद्धांतों के लिए एक अधिवक्ता एफ को अपने मुवक्किल के लिए राहत की अंधी खोज में डूबे रहने की आवश्यकता नहीं है, इस खोज में संस्थान की गरिमा का उल्लंघन नहीं किया जा सकता है क्योंकि कृष्णा लायर, जे ने बार काउंसिल ऑफ महाराष्ट्र बनाम, M.V.Dabhotkar[5] में कहा है कि "कानून कोई व्यापार नहीं है, कोई व्यापार नहीं है"।

25. इस बिंदु पर यह भी ध्यान देंने योग्य है कि सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता 'जी' में विवियन बोस, जे. के प्रस्फुटित करने वाले शब्द जी, जिन्होंने पुनः[6] स्पष्ट कियाः

“सेना की भाषा का उपयोग करने के लिए, इस न्यायालय के एक अधिवक्ता से हर समय एक "अधिकारी और सज्जन" के रूप में अपनी स्थिति

5 **(1976) 2 एस. सी. सी. 291**

6 **ए. आई. आर. 1954 एस. सी. 557**

के अनुरूप व्यवहार करने की अपेक्षा की जाती है।

26. यह 1925 में है कि वर्जीनिया लॉ रिव्यू में प्रकाशित 'द लॉयर एज एन ऑफिसर ऑफ द कोर्ट'[7] शीर्षक से एक लेख में स्पष्ट रूप से निर्धारित किया गया है कि वकील से क्या उम्मीद की जाती है जो अपने शब्दों में सबसे अच्छा हैः

> "न्यायाधीशालय के प्रति वकील के कर्तव्य सीधे उस संबंध से उत्पन्न होते हैं जो वह न्यायाधीश के प्रशासन में एक अधिकारी के रूप में न्यायाधीशालय के साथ रखता है। कानून केवल एक निजी काम नहीं है, बल्कि एक ऐसा पेशा है जिसे राज्य की न्यायिक प्रणाली का एक अभिन्न अंग होने का गौरव प्राप्त है। इसलिए न्यायालय के एक अधिकारी के रूप में वकील न्यायालय की गरिमा और अखंडता को बनाए रखने के लिए बाध्य है; हर समय शब्दों और कार्यों दोनों में न्यायालय के प्रति सम्मान का प्रयोग करने के लिए; अपने मुवक्किल के मामले से संबंधित सभी मामलों को खुले तौर पर प्रस्तुत करने के लिए, न्यायाधीश या जूरी पर निजी प्रभाव डालने के किसी भी प्रयास से बचने के लिए सावधान रहना; और न्यायालय के साथ सभी व्यवहारों में स्पष्ट और स्पष्ट होना, "किसी भी छल, अधिरोपण या चोरी का उपयोग नहीं करना", जैसे कि गवाहों को गलत तरीके से पेश करना या पूर्व निर्णय को गलत तरीके से उद्धृत करना। "दिसंबर, 1911 में मिल्वौकी काउंटी बार एसोसिएशन के समक्ष एक संबोधन में डॉर्फलर कहते हैं, "यह हमेशा समझना चाहिए कि कानून का पेशा पुरुषों के बीच न्यायाधीश के प्रशासन में सहायता करने के उद्देश्य से स्थापित किया गया है। न्यायाधीश के उचित प्रशासन का मतलब यह नहीं है कि एक वकील को मुकदमा जीतने में सफल होना चाहिए।

7 **"वर्जीनिया लॉ रिव्यू, Vol.11, नंबर 4 (फरवरी 1925) पीपी. 263-277 एच**

इसका मतलब है कि उसे अपने मुवक्किल के मामले को ठीक से प्रस्तुत करने के उद्देश्य से उपलब्ध और वैध तथ्य और कानून के माध्यम से अदालत के ध्यान में हर चीज को उचित रूप से रखना चाहिए।

जहाँ तक उनके मुवक्किल का संबंध है, उनका कर्तव्य केवल मामले में अपना पक्ष वैध रूप से प्रस्तुत करना है। जहाँ तक जनता का संबंध है और जहाँ तक वह न्यायाधीशालय का अधिकारी है, उसका कर्तव्य न्यायाधीश के प्रशासन में सहायता और सहायता करना है। ”

इस संबंध में श्री वारवेल के सामयिक शब्दों को भी अच्छी तरह से याद किया जा सकता हैः

“लेकिन वकील अकेले एक सज्जन नहीं है; वह न्यायाधीश मंत्री है। उनका पद उच्च नैतिक कर्तव्यों और गंभीर जिम्मेदारियों को लागू करता है, और उन्हें इन सभी मामलों को सख्ती से पूरा करने के लिए आयोजित किया जाता है। उसे विशाल हित सौंपे जाते हैं; उस पर विश्वास थोपा जाता है; जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति उसकी देखभाल के लिए प्रतिबद्ध होती है, उसे उन जिम्मेदारियों के बराबर होना चाहिए जो वे पैदा करते हैं, और यदि वह अपने विश्वास के साथ विश्वासघात करता है, अपने कर्तव्यों की उपेक्षा करता है, छल करता है, या बुराई को बढ़ावा देता है, तो सबसे कठोर दंड लगाया जाना चाहिए और उसका नाम सूची से हटा दिया जाना चाहिए।”

कि वकील का अपने पेशे और उसके प्रति उच्च कर्तव्य है। बार के उनके साथी सदस्य एक स्पष्ट सत्य हैं, उनका पेशा उनका गौरव होना चाहिए, और इसके सम्मान को बनाए रखना उनकी मुख्य चिंताओं में से एक होना चाहिए। “श्री अलेक्जेंडर एच. रॉबिन्स घोषणा करते हैं, "अधिवक्ता के आकलन

में उनके पेशे की तुलना में देश और देश के उन पवित्र संबंधों के बाद कुछ भी बेहतर नहीं होना चाहिए। "वह उनके लिए पृथ्वी की संस्थाओं में 'दस हजार में सबसे अच्छी' होनी चाहिए। उसे हर जगह उसके लिए खड़ा होना चाहिए और उसके सम्मान पर किसी भी हमले से नाराज होना चाहिए-जैसा कि वह करेगा अगर वही हमला उसके अपने उचित नाम और प्रतिष्ठा के खिलाफ किया जाए। उसे उसे अपने हृदय के पवित्र स्थानों पर सिंहासन पर बिठाना चाहिए, और उसे निरंतर भक्ति का धूप चढ़ाना चाहिए।

क्योंकि वह एक ईर्ष्यालु मालकिन है। "

एक बार फिर, यह ध्यान में रखा जाना चाहिए कि न्यायाधीशों का चयन वकीलों के रैंक से किया जाता है। पीठ की शुद्धता बार की शुद्धता पर निर्भर करती है।

"यह तथ्य कि सरकार के समन्वित विभागों में से एक का प्रशासन केवल एक पेशे से चुने गए पुरुषों द्वारा किया जाता है, उस पेशे को एक निश्चित श्रेष्ठता देता है जो नैतिकता के उच्च मानक के साथ-साथ बौद्धिक उपलब्धियों की मांग करता है। न्यायपालिका की अखंडता राष्ट्र की सुरक्षा है, लेकिन न्यायाधीशों का चरित्र व्यावहारिक रूप से वकीलों का चरित्र है। जैसे जन्म लेता है। एक अवक्रमित बार अनिवार्य रूप से उत्पादन करेगा। एक अपमानित पीठ, और निश्चित रूप से हम एक प्रबुद्ध, विद्वान और नैतिक वकील के रैंक से तैयार न्यायपालिका में उच्चतम उत्कृष्टता प्राप्त करने की उम्मीद कर सकते हैं। "

27. उन्होंने अपने लेख को निम्नलिखित शब्दों में समाप्त कियाः

"कोई भी मुवक्किल, कॉर्पोरेट या व्यक्ति, चाहे वह कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, न ही कोई नागरिक या राजनीतिक कारण, चाहे वह

कितना भी महत्वपूर्ण हो, प्राप्त करने का हकदार है, न ही किसी वकील को ऐसी कोई सेवा या सलाह देनी चाहिए जिसमें कानून के प्रति बेवफाई हो, जिसके मंत्री हम हैं, या न्यायिक पद का अनादर, जिसे हम बनाए रखने के लिए बाध्य हैं, या किसी सार्वजनिक पद या निजी ट्रस्ट का प्रयोग करने वाले किसी व्यक्ति या व्यक्ति का भ्रष्टाचार, या जनता के साथ धोखा या विश्वासघात। इस तरह की कोई अनुचित सेवा या सलाह देते समय, वकील कठोर और न्यायसंगत निंदा का आह्वान करता है और उसके योग्य होता है। तदनुसार, वह अपने पेशे के सम्मान और अपने मुवक्किल के सर्वोत्तम हितों को आगे बढ़ाता है जब वह सेवा प्रदान करता है या मुवक्किल को प्रभावित करने के लिए सलाह देता है और नैतिक कानून के सख्त सिद्धांतों का सटीक पालन करता है। उसे अपने मुवक्किल को अधिनियम का पालन करने के लिए भी सलाह देनी चाहिए, हालांकि जब तक किसी अधिनियम का सक्षम निर्णय द्वारा अर्थ और व्याख्या नहीं की जाती है, तब तक वह स्वतंत्र है और इसकी वैधता के बारे में सलाह देने का हकदार है और जिसे वह ईमानदारी से इसका उचित अर्थ और विस्तार मानता है। लेकिन, सर्वोपरि एक वकील को अपना सर्वोच्च सम्मान निजी विश्वास और सार्वजनिक कर्तव्य के प्रति निष्ठा के लिए एक योग्य प्रतिष्ठा में, एक ईमानदार व्यक्ति के रूप में और एक देशभक्त और वफादार नागरिक के रूप में मिलेगा। ”

28. कानूनी सिद्धांतों की जांच करने पर एक महत्वपूर्ण मुद्दा सामने आता हैःअदालत में उपस्थित बार के प्रतिनिधियों द्वारा समर्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री के. के. वेणुगोपाल की एक भावपूर्ण याचिका में जो अवमानकर्ता ने शुरू किया था, उसका अंत क्या होना चाहिए, जो अवमानकर्ता के लिए उनकी उपस्थिति को चिह्नित करता है। हम इस तरह की याचिका पर उचित विचार करने के लिए इच्छुक हैं, लेकिन

अवमानकर्ता को बिना किसी परिणाम के मुक्त करने के लिए खुद को मनाने में असमर्थ हैं। इस प्रकार हम अवमानना अधिकार क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए इच्छुक नहीं हैं, सिवाय इसके कि अवमानना करने वाले को आगाह किया जाए कि यह इस तरह के दुस्साहस का पहला और अंतिम समय होना चाहिए। लेकिन मामला केवल इतने पर ही सीमित नहीं रह सकता।

29. यह एक निर्दोष कार्य नहीं था, एक हानिरहित प्रयास था, बल्कि एक दुर्भाग्यपूर्ण रास्ते पर चलने का एक सुविचारित निर्णय था, जिसे मौजूदा अधिवक्ता-ऑन-रिकॉर्ड करने के लिए तैयार नहीं थे। इसका उद्देश्य केवल किसी तरह पीठ को स्थानांतरित करने की मांग करके मुवक्किल की सहायता करना था। पंजीकरण के खिलाफ लगाए गए आरोप झूठे थे और अदालत के खिलाफ आरोप थे। यह प्रयास विफल रहा। प्रत्येक क्रिया का एक परिणाम होता है। इस प्रकार अवमानकर्ता को अपने आचरण के कुछ परिणामों का सामना करना पड़ता है।

30. हमारा विचार है कि नियमों के तहत रिकॉर्ड पर अधिवक्ता होने के विशेषाधिकार का स्पष्ट रूप से अवमानक द्वारा दुरुपयोग किया गया है। यह आचरण सर्वोच्च न्यायालय में एक अधिवक्ता से बहुत कम एक अधिवक्ता-ऑन-रिकॉर्ड नहीं बन रहा था।

31. इस संदर्भ में, हम उक्त नियमों के आदेश IV के नियम 10 का उल्लेख करना चाहेंगे जो निम्नानुसार हैः

"10.जब, किसी व्यक्ति की शिकायत पर या अन्यथा, न्यायालय की राय होती है कि कोई अधिवक्ता-ऑन-रिकॉर्ड कदाचार या अधिवक्ता-ऑन-रिकॉर्ड के अनुपयुक्त आचरण का दोषी रहा है, तो न्यायालय रिकॉर्ड पर अधिवक्ताओं के रजिस्टर से उसका नाम स्थायी रूप से या ऐसी अवधि के लिए हटाने का आदेश दे सकता है जो न्यायालय

उचित समझे और पंजीयक उसके बाद उक्त तथ्य को भारतीय बार काउंसिल और संबंधित राज्य बार काउंसिल को रिपोर्ट करेगाः

बशर्ते कि न्यायालय, ऐसा आदेश देने से पहले, ऐसे अधिवक्ता को "न्यायालय के समक्ष या मुख्य न्यायाधीश द्वारा गठित की जाने वाली विशेष पीठ के समक्ष वापसी योग्य सम्मन देना जारी करेगा, जिसमें अधिवक्ता से सम्मन देना में आरोपित मामलों में डी के खिलाफ कारण दिखाने की आवश्यकता होगी, और सम्मन देना, यदि व्यवहार्य हो, तो सम्मन देना जारी करने के समय न्यायालय के समक्ष किसी भी शपथ पत्र या बयान की प्रतियों के साथ व्यक्तिगत रूप से उस पर भेजा जाएगा।

स्पष्टीकरण - इन नियमों के प्रयोजन के लिए, किसी अधिवक्ता के कदाचार या अनुचित आचरण में शामिल होंगे -

(ए) मामले की कार्यवाही में आगे किसी भी भागीदारी के बिना एक वकील-ऑन-रिकॉर्ड द्वारा केवल नाम उधार;

(ख) जब मामला सुनवाई के लिए लिया जाता है तो बिना किसी उचित कारण के अदालत से अधिवक्ता की अभाव; और

(ग) अदालत में वास्तविक उपस्थिति की अधिवक्ता-ऑन-रिकॉर्ड द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित उपस्थिति पर्ची प्रस्तुत करने में विफलता।

उपरोक्त नियम यह स्पष्ट करता है कि चाहे किसी व्यक्ति की शिकायत पर या अन्यथा, कदाचार या रिकॉर्ड पर अधिवक्ता के अनुपयुक्त आचरण के मामले में, न्यायालय स्थायी रूप से या एक निर्दिष्ट अवधि के लिए अधिवक्ता-ऑन-रिकॉर्ड के रजिस्टर से उसका नाम हटाने का आदेश दे सकता है। हम अधिवक्ता के रूप में कार्य करने के अधिकार और किसी भी राज्य बार काउंसिल की सूची में दर्ज नाम का उल्लेख नहीं कर रहे हैं, जो एक आवश्यक आवश्यकता है, इससे पहले कि कोई व्यक्ति

अधिवक्ता-ऑन-रिकॉर्ड की परीक्षा दे। वर्तमान मामला स्पष्ट रूप से ऐसा है जहां इस न्यायालय की राय है कि अवमानकर्ता का आचरण रिकॉर्ड पर अधिवक्ता के लिए अशोभनीय है। परंतुक की पूर्व-अपेक्षाओं को पूरा किया जाता है, क्योंकि मुख्य न्यायाधीश द्वारा स्वयं पीठ का गठन किया जाता है, और अवमानकर्ता को कहीं अधिक गंभीर परिणामों के बारे में पता होता है, जो उसके सामने आ सकते थे। याचिकाकर्ता का प्रतिनिधित्व करने वाले विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता उसे अदालत की दया पर छोड़ दिया है। हमने अनुरोध को काफी हद तक स्वीकार कर लिया है लेकिन अवमानकर्ता पर कम परिणाम लगाए गए हैं।

32. इस प्रकार हमारा विचार है कि कार्रवाई का उचित तरीका यह होगा कि अवमानकर्ता को आदेश की तारीख से एक महीने की अवधि के लिए रिकॉर्ड पर अधिवक्ता के रूप में अभ्यास करने की अनुमति नहीं है। एक दर्दनाक कार्य किया जाना था और किया जाता है।

33. हम आशा करते हैं कि याचिकाकर्ता और अन्य अधिवक्ताओं दोनों के लिए जो अदालत के नैतिक अभ्यास का भंग करने के लिए भी मुवक्किल के हित को सर्वोपरि मान सकते हैं, यह एक सावधानी होगी। हम और नहीं कहते हैं।

अंकित ज्ञान

अवमानना याचिका का निपटारा किया गया।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल '**सुवास**' की सहायता से अनुवादक द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण : यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।